मुसीबत है मोबाइल गेम

सेवाओं, सुविधाओं और मनोरंजन को सुलभ बनाने में डिजिटल तकनीक और इंटरनेट ने बड़ी भूमिका निभायी है. इससे जानकारी और सूचनाएं जुटाना भी आसान हुआ है. वीडियो, कंप्यूटर और मोबाइल के खेल इस प्रक्रिया के अहम हिस्से हैं, लेकिन इनके नकारात्मक प्रभावों की अनदेखी करना नुकसानदेह हो सकता है. दो साल पहले ब्लू व्हेल नामक खेल ने बच्चों और किशोरों को आत्महत्या तक करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया था. अब अनेक खेलों पर वैसे ही आरोप लगने लगे हैं. पिछले महीने गुजरात के स्कूलों में बेहद लोकप्रिय मोबाइल गेम पीयूबीजी को प्रतिबंधित किया गया है. अब दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसके साथ कुछ अन्य खेलों को चिह्नित करते हुए रोक की गुहार लगायी है. इन खेलों की लत के शिकार बच्चों में पढ़ाई को लेकर उदासीनता बढ़ रही है, व्यवहार में उग्रता आ रही है तथा वे अवसाद के भी शिकार हो रहे हैं. मोबाइल के बहुत अधिक इस्तेमाल से बच्चों की मानसिक क्षमता कम होने के साथ मस्तिष्क में ट्यूमर और कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं. पिछले साल अमेरिका के मिशिगन विवि ने जानकारी दी थी कि पांच साल से कम आयु के बच्चों के लिए बनाये गये अधिकतर लोकप्रिय एप साथ में भ्रामक विज्ञापन भी संलग्न करते हैं, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं हैं. अनेक शोध इंगित कर चुके हैं कि बड़े बच्चों के लिए ऐसे विज्ञापन परोसे जा रहे हैं, जो भावनात्मक और मानसिक स्तर पर घातक हो सकते हैं. बच्चों को डराने-धमकाने और उनके शोषण के मामले भी सामने आते रहते हैं. एक अध्ययन के अनुसार, हमारे देश में 2017 में 22.2 करोड़ लोगों ने रोजाना औसतन 42 मिनट समय खेलों में लगाया था. पीयूबीजी पिछले साल मार्च में आया था और आज इसके कुल खिलाड़ियों में तीन-चौथाई लोग मोबाइल पर इसे खेलते हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इन खेलों पर देशव्यापी रोक की मांग की है. दुर्भाग्य है कि कई स्कूलों द्वारा चेतावनी देने के बाद भी अभिभावक बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं. माता-पिता द्वारा डांटने पर बच्चों में आक्रामकता और आत्महंता जैसी प्रवृत्तियां भी आ रही हैं. जाहिर है, खतरनाक मोबाइल खेलों के चंगुल से बच्चों को छुड़ाना आसान नहीं है. यह मसला सिर्फ डांटने-डपटने से हल नहीं होगा. अभिभावकों और शिक्षकों को लत के शिकार बच्चों की पहचान कर उन्हें मनोवैज्ञानिक मदद के जरिये बाहर निकालना होगा. स्कूलों और परिवारों में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है. प्रतिबंध लगाने का विकल्प भी है, पर अगर बच्चे के पास मोबाइल होगा, तो वह इसका इस्तेमाल करेगा ही. डिजिटल मामलों में कानूनी स्तर पर पाबंदी कारगर नहीं होती है, क्योंकि इंटरनेट के अथाह समंदर में खतरनाक खेलों और वेबसाइटों की भरमार है. ऐसे में बच्चों को समझाने-बुझाने तथा मनोरंजन के स्वस्थ संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए.

खतरनाक मोबाइल खेलों के चंगुल से बच्चों को छुड़ाना आसान नहीं है. अभिभावकों और शिक्षकों को लत के शिकार बच्चों की पहचान करके उन्हें मनोवैज्ञानिक मदद के जरिये बाहर निकालना होगा.

जल एक ज्वलंत मुद्दा बने

अजीत रानाडे

सीनियर फेलो, तक्षशिला इंस्टिट्यूशन

editor@thebillionpress.org

अगले आम चुनाव हमसे अब भी तीन महीने दूर हैं. चुनाव विशेषज्ञ बताते हैं कि आम चुनाव का मुद्दा हमेशा ही अर्थव्यवस्था से संबद्ध हुआ करता है. हाल के केंद्रीय बजट ने किसानों एवं निम्नतर आयकर दाताओं को उदार राहत मुहैया की है, पर केवल वक्त ही यह बता सकेगा कि यह कदम सत्तासीन पार्टी को कोई लाभ पहुंचा सकेगा अथवा नहीं. जीडीपी को लेकर पुनरीक्षित आंकड़ों का निष्कर्ष यह है कि पिछले चार वर्षों ने असाधारण आर्थिक विकास देख कर भारत को विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक बना डाला है. किंतु उद्योगों को बैंक ऋण, निजी व्यय तथा निर्यात जैसे अन्य संकेतक इन संख्याओं की पुष्टि नहीं करते. जीडीपी के आंकड़ों पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अभी स्वयं ही किसी स्वतंत्र सदस्य की उपस्थिति से वंचित है.

जो भी हो, कृषि संकट की वास्तविकता से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं और वाकई यह केंद्रीय चुनावी मुद्दा होगा. ग्रामीण तथा कृषि अर्थव्यवस्थाएं एक-दूजे में गुंथित हैं, जिन्हें अल्पावधि में ही बड़ी नीतिगत तथा राजकोषीय सहायता की जरूरत है. पर मध्यावधि एवं दीर्घावधि में कृषि संकट का समाधान कृषि के बाहर ही मिल सकता है. यह दूसरी बात है कि चुनाव हमेशा अल्पावधि दृष्टि लेकर होते हैं, जिनमें सारा जोर फौरी उपायों पर होता है.

यही वह बिंदु है, जहां किसानों की सबसे बड़ी चुनौती की चर्चा की जानी चाहिए. पिछले जून से लेकर सितंबर के महीनों तक अखिल भारतीय स्तर पर बारिश में नौ प्रतिशत की कमी रही. अक्तूबर से दिसंबर के मॉनसून-पश्चात काल के दौरान महाराष्ट्र में यह कमी 44 प्रतिशत की थी. यदि पूरे देश के सभी हिस्सों की बात करें, तो उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश की कमी 45 प्रतिशत, मध्य भारत में 51 प्रतिशत, दक्षिणी प्रायद्वीप में 36 प्रतिशत एवं पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में 51 प्रतिशत रही. ये सभी आंकड़े भारतीय मौसम विज्ञान प्रभाग के हैं. यह अभी ही साफ हो चुका है कि इस कमी से रबी की फसलों पर बुरा असर पड़ेगा. गेहूं की उपज गिरेगी, जिससे उसकी कीमतें चढ़ सकती हैं. जाहिर है कि किसानों के लिए यह खबर अच्छी ही कही जायेगी, क्योंकि अतीत में उन्हें मूल्यों की गिरावट झेलनी पड़ी है. पर उन सभी क्षेत्रों के लिए, जो सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं, यह परिदृश्य परेशानी का सबब है. चूंकि अगला मॉनसून अब भी चार महीने दूर है, अतः जलाशयों के जलस्तर को भी देखना होगा, क्योंकि उसके गिरने से न केवल सिंचाई, बल्कि पेयजल आपूर्ति तथा पन-बिजली उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है. नर्मदा जलाशय का जल जून के अंत तक नहीं टिक सकेगा. महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में तो अभी से टैंकरों द्वारा पेय जल की ढुलाई शुरू हो गयी है.

जल संकट की प्रतिवर्ष पैदा होनेवाली ऐसी पृष्ठभूमि में किसी भी व्यक्ति को पिछले जून महीने में नीति आयोग द्वारा भारत के जल संकट पर जारी की गयी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जो यह कहती है कि अगले दो वर्षों में भारत के 21 ऐसे शहरों में, जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या दस लाख से ऊपर है, 'जल समाप्त हो जायेगा.' इसकी वजह यह है कि उनके भू-जल स्रोत के पुनर्भरण की गति उसके उपयोग से कम है. तथ्य तो यह है कि स्थितियां इससे भी खासी आगे जा चुकी हैं. कपास तथा ईंख जैसी जल पिपासु फसलों की सिंचाई के अतिरिक्त उद्योगों एवं आवासीय उपयोग के लिए नलकूपों का उपयोग सीमा पार कर चुका है. यह सदमे की ही बात है कि सिंचित कृषि का 60 प्रतिशत तथा पेय जल आपूर्ति का 85 प्रतिशत से भी अधिक भू-जल स्रोत पर ही निर्भर है. विश्व बैंक के अनुसार, भारत भूमि से प्रतिवर्ष 250 घन किलोमीटर जल की निकासी करता है, जो विश्व के वार्षिक भू-जल आपूर्ति का लगभग एक-चौथाई है. नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि 60 करोड़ भारतीय उच्च से लेकर आत्यंतिक जल संकट के शिकार हैं, जो उसकी उपलब्धता तथा गुणवत्ता से संबद्ध है. जल प्रदूषण जल वाहित रोग तथा रोकी जा सकनेवाली मौतों की वजह भी है.

जल उपलब्धता में कमी से खाद्य सुरक्षा तथा औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होता है. फिर जल संकट कई विसंगतियों को भी जन्म दे सकता है, जैसे जब टैंकरों द्वारा लाया जल ऊंची कीमतों पर बिकने लगता है, तो किसान अपने नलकूपों से सिंचाई के बदले उससे निकला जल बेचने में ज्यादा रुचि ले सकते हैं. कई चुनाव-पूर्व सर्वेक्षणों से यह तथ्य निकलकर आ चुका है कि मतदाताओं के लिए पेयजल उपलब्धता एक ऊंची प्राथमिकता है.

जल संकट भारत की प्रमुख चुनौतियों में एक है और इससे पैदा जोखिम ऊंची, समावेशी तथा सतत विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं. इस चुनौती से निबटने हेतु बहुमुखी दृष्टि अपनायी जाने की आवश्यकता है.

जल संकट भारत की प्रमुख चुनौतियों में एक है और इससे पैदा जोखिम ऊंची, समावेशी तथा सतत विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं. इस चुनौती से निबटने हेतु बहुमुखी दृष्टि अपनायी जाने की आवश्यकता है. पहली जरूरत तो यह कि आक्रामक मांग पक्ष प्रबंधन के कदम उठाये जायें, जैसे पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग), वर्षाजल संचय, शून्य-निस्सरण (जीरो-डिस्चार्ज) औद्योगिक उपयोग, आदि. दूसरी, प्रभावित क्षेत्रों के उपज ढांचे से ईंख जैसी जल-पिपासु फसलों को हटाया जाना चाहिए. तीसरी, जल उपयोग हेतु उचित मूल्य निर्धारण, कृषि उपयोग पर सब्सिडी में कमी लाना और उस हेतु मुफ्त विद्युत आपूर्ति की परंपरा खत्म करना, क्योंकि उससे जरूरत से ज्यादा भू-जल दोहन को बढ़ावा मिलता है. इसके अतिरिक्त, पानी-पंचायत और जल उपयोगकर्ता संघ की स्थापना जैसी अवधारणाओं को लागू कर भू-जल के स्वामित्व तथा प्रबंधन को निजी प्रबंधन से हटाकर सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत लाया जाना जरूरी होगा. सच तो यह है कि हमें एक ऐसे कानून की जरूरत है, जो भू-जल को निजी संपत्ति की बजाय सामूहिक संसाधन मानता हो. पांचवी जरूरत अपने नजरिये में फर्क लाते हुए जल सघन उपजों के उदार आयात को अनुमति देते हुए जल समृद्ध विदेशी स्थलों पर कॉरपोरेट कृषि निवेश को बढ़ावा देना होगा.

तात्पर्य यह है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब शून्य खाद्य आयात नहीं, बल्कि घरेलू एवं आयात स्रोतों का एक विवेकशील मिश्रण अपनाना है. जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार याद दिलाया करते हैं, जल की प्रत्येक बूंद से अधिक फसल सुनिश्चित की जानी चाहिए. यह संभव है कि अगले आम चुनाव में जल कोई ज्वलंत मुद्दा भले न बने, पर निश्चित रूप से यह अत्यावश्यक राष्ट्रीय चुनौतियों में शामिल तो है ही.

(अनुवाद: विजय नंदन)

बोधि वृक्ष

प्रकृति के नियम

प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति, पर्यावरण और जीवन है, इसलिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार करें, जो इनमें थोड़े-बहुत अंतर को दर्शाते हैं. मनुष्य, पेड़-पौधे और पशुओं में केवल इंद्रियों का अंतर है. मनुष्य के पास दस इंद्रियां हैं, तो पशुओं के पास दस से कम और पेड़ों के पास उससे भी कम. इसलिए विज्ञान कहता है कि पेड़-पौधे भी हंसते-रोते हैं. लकड़हारे को देख कर वृक्षों के पत्ते सिहर उठते हैं, वे मुरझा जाते हैं. ये वृक्ष और पहाड़ मनुष्य के समान जीव ही हैं, तो फिर मनुष्यों की प्रगति के नाम पर इन वृक्षों और पहाड़ों का नाश कितना उचित है? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें निरोगी बनाये रखने के लिए जरूरी है. यूनान के प्रसिद्ध हकीम लुकमान पेड़-पौधों से उनकी उपयोगिता पूछ कर मनुष्य का इलाज किया करते थे. भारत में भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्रकृति के आशीर्वाद पर ही निर्भर है. इसका एक कारण यह भी है कि मनुष्य का शरीर और प्रकृति की वनस्पति, दोनों एक ही तत्व से बने हुए हैं. जो तत्व इन वृक्षों और वादियों में हैं, वही तत्व मनुष्य में भी हैं. इसलिए दोनों के जीवन में साम्य है. इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य को दीर्घायु बनना है और स्वस्थ रहना है, तो प्रकृति और पर्यावरण की गोद में ही वह स्वस्थ और सुरक्षित रह सकता है. आज प्रगति के पंख पर उड़नेवाले पश्चिम देश के लोग भी अब प्रकृति और पर्यावरण के आंचल में प्राणशक्ति खोजने में लगे हुए हैं. अब उन्हें भी बोध हो गया है कि प्रगति की दौड़ में दौड़ कर प्राणशक्ति को गंवा देना उचित नहीं है. अगर जीवन चाहिए, तो हमें प्रकृति की ओर लौटना ही पड़ेगा. सच कहें तो प्रकृति, पर्यावरण, जीवन और परमात्मा कोई अलग-अलग चीजें नहीं हैं. अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है. अगर मानव जाति इस संबंध में गहराई से सोचे और पेड़-पौधों और प्रकृति के शाश्वत नियमों से छेड़छाड़ करना बंद कर दे, तो यही प्रकृति उन्हें अपनी गोद में भरकर एक ऊर्जावान और निरोगी जीवन प्रदान करेगी. प्रकृति जीवन देती है, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए. वसंत आनेवाला है, इससे प्रेम करें.

आचार्य सुदर्शन

अवैध इमिग्रेशन पर लगे रोक

अभिषेक कुमार

टिप्पणीकार

abhi.romi20@gmail.com

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर देश में ही हजारों लोग ठगे जाते हैं. कबूतरबाजी यानी अवैध इमिग्रेशन के शिकार इन्हीं लोगों में से कुछ लोग जब किसी तरह विदेश पहुंच जाते हैं, तो वहां उनके रोजगार से लेकर जिंदगी तक का कोई ठिकाना नहीं होता. ताजा घटनाक्रम अमेरिका में खड़ी की गयी एक फर्जी यूनिवर्सिटी के जरिये 129 भारतीय छात्रों की धर-पकड़ का है. बताया गया है कि ये भारतीय छात्र वहां एक इमिग्रेशन रैकेट के जरिये पहुंचे थे. आरोप है कि ये छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए रजिस्टर्ड थे, लेकिन वे अमेरिका में काम कर रहे थे. यह भी बताया गया कि इस फर्जी यूनिवर्सिटी को एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत 2015 में अमेरिका ने खुद बनाया था. अमेरिका के मिशिगन राज्य में 'यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंग्टन' को अमेरिकी सुरक्षा बलों के अंडरकवर एजेंट चला रहे थे, ताकि पैसे के बदले अवैध प्रवास की चाह रखनेवालों को पकड़ा जा सके. इस मामले में भारत ने राजनयिक विरोध दर्ज कराया है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वादा किया है कि इन भारतीय छात्रों को कानूनी मदद दिलायी जायेगी.

अमेरिका में 'पे एंड स्टे' गिरोह के भंडाफोड़ का यह मामला नया नहीं है. साल 2016 में वीजा घोटाले में 306 भारतीय छात्रों को अमेरिका से निकाल दिया गया था. अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टीगेशन (एचएसआई) ने लंबी जांच के बाद कहा था कि इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न न्यूजर्सी (यूएनएनजे) में दाखिला लिया था. दाखिले के लिए सभी छात्रों ने फर्जी तरीके से अमेरिका का वीजा हासिल किया था. उस वक्त भी बताया गया था कि एचएसआई ने वीजा घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए ही यूएनएनजे की स्थापना की थी. यह एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन था. इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करने के लिए एचएसआई ने स्टिंग के तहत कुल 1,076 विदेशी नागरिकों की पहचान की, जिनमें 306 भारतीय छात्र थे. यह भी पता चला कि कई शिक्षण संस्थाएं दरअसल वीजा के फर्जीवाड़े में ही संलिप्त हैं.

बेरोजगारी से जूझ रहे हमारे देश में रोजगार की तलाश में विदेश जाने की चाहत नयी नहीं है. इससे पहले खाड़ी देशों में गये भारतीय श्रमिक के शोषण की अंतहीन कहानियां सामने आती रही हैं. कई बार प्लेसमेंट एजेंट विदेश पहुंचे मजदूरों से मारपीट करते हैं, उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं और इसके बाद भी अगर किसी तरह ये मजदूर कोई काम पाने में कामयाब रहे, तो सऊदी अरब के निताकत जैसे कड़े श्रमिक कानून उनकी नौकरी में आड़े आते रहते हैं. वहां कामगारों के हक, काम के घंटे, छुट्टी में स्वदेश जाने के इंतजाम और अवकाश पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है. दो साल पहले 2016 में आरटीआई से मिली जानकारी से पता चला था कि भारत से कुल 112 देशों में प्रवासी कामगार जाते हैं, जिनमें से 6,635 कामगार भारतीय विदेशी जेलों में उस वक्त बंद थे (यह जानकारी 'माइग्रेंट्स राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष पी नारायण स्वामी ने जुटायी थी). सच है कि ज्यादातर मामलों में हमारी सरकार न तो इन कैदियों की तरफ ध्यान दे पाती है और न ही वह उन गरीब प्रवासियों की सुध ले पाती है, जो अवैध रूप से विदेश जाते हैं. लगता है कि सरकार को फिक्र सिर्फ प्रवासियों से मिलनेवाले पैसे की है, उनके हितों से उसका कोई सरोकार नहीं है.

खाड़ी देशों में काम करने गये भारतीय मजदूरों के पास अक्सर ना तो कोई पेशेवर डिग्री होती है और न ही उनके पास विदेश में प्रवास के वैध दस्तावेज होते हैं. कबूतरबाजी यानी प्लेसमेंट एजेंसियों के फर्जीवाड़े से इनमें से जो कुछ मजदूर खाड़ी मुल्कों में पहुंच जाते हैं, वे वहां मिलनेवाले दीनार या रियाल की मदद से कुछ ठीक-ठाक गुजारा करते रहे हैं और बचायी गयी रकम भेज कर अपने घरवालों और सरकार तक की मदद करते रहे हैं. लेकिन, सऊदी में अप्रैल, 2013 में लागू किये गये श्रम कानून- निताकत ने ऐसे श्रमिकों के लिए दो ही विकल्प छोड़े- या तो वे किसी तरह अपने लिए वैध दस्तावेजों का इंतजाम करें या स्वदेश लौट जायें. उस वक्त ज्यादातर श्रमिक स्वदेश लौट आये थे.

विदेशों में रोजगार के लिए गये एक करोड़ 10 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों के लिए संकट यह है कि उन्हें स्थानीय श्रम कानूनों में होनेवाले फेरबदल के साथ-साथ सिकुड़ते रोजगार विकल्पों की समस्या, गृहयुद्ध और आतंकवाद से भी जूझना पड़ता है. दरअसल, पूरी दुनिया का रोजगार मार्केट सिकुड़ रहा है. हर जगह स्थानीय लोगों को रोजगारों में प्राथमिकता देने की मांग उठ रही है. ऐसे में सवाल यह है कि विदेश गये अनिवासी भारतीयों के हित में हमारी सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? इसका पहला उपाय है देश से बाहर नौकरी जानेवाले हर शख्स के वैध प्रवासन की व्यवस्था करना. सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकार को अवैध ढंग से चलनेवाली गैरकानूनी माइग्रेशन के चोर दरवाजे को बंद करने में सख्ती दिखानी होगी. उसे यह भी गौर करना चाहिए कि जिन देशों में भारतीय कामगार व आईटी पेशेवर जा रहे हैं, क्या उनके माइग्रेशन में वहां के वीजा और श्रम कानूनों से कोई खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है. यदि उन देशों में कोई समस्या नजर आये या वहां के वीजा और श्रम कानूनों में कोई बड़ी तब्दीली नजर आये, तो ऐसे लोगों को वहां जाने से रोक लेना चाहिए. ऐसी व्यवस्था नहीं करने पर ही वहां उनके साथ होनेवाली समस्या उन लोगों के परिवारों समेत खुद सरकार के लिए भी संकट का कारण बन जाती है.

दरअसल, पूरी दुनिया का रोजगार मार्केट सिकुड़ रहा है. हर जगह स्थानीय लोगों को रोजगारों में प्राथमिकता देने की मांग उठ रही है. ऐसे में सवाल यह है कि विदेश गये अनिवासी भारतीयों के हित में हमारी सरकार को क्या उपाय करने चाहिए?

आपके पत्र

लोकतंत्र को किससे खतरा है?

'आज लोकतंत्र खतरे में है ' का स्वर समाचार पत्रों और टीवी समाचार माध्यमों में सबसे ज्यादा आ रहे हैं. विभिन्न राजनैतिक दलों (सत्तासीन और विपक्ष दोनों ही तरफ से) लोकतंत्र के शुभचिंतकों, लेखकों, पत्रकारों और सामाजिक संगठनों द्वारा व्यक्त की जा रही है. आखिर अभी देश में ऐसा क्या हो गया कि हमारे लोकतंत्र को ग्रहण लग गया? अभी-अभी पश्चिम बंगाल में हुई दुखद घटना में केंद्र में सत्तारूढ़ दल और लगभग सभी विपक्षी पार्टियां समवेत स्वर में, दोनों तरफ से 'लोकतंत्र खतरे में है', की बात एक-दूसरे पर आरोपित कर रही है. पश्चिम बंगाल के डीजीपी पर छापामार स्टाइल में कार्यवाही करने गयी सीबीआइ को कोलकाता पुलिस के माध्यम से रोककर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक कार्य किया है, परंतु केंद्र सरकार के निर्देशों पर बगैर किसी समुचित कागजात के डीजीपी स्तर के अधिकारी के घर रात में छापा मारने गयी सीबीआइ और केंद्र सरकार ने कम अलोकतांत्रिक कार्य नहीं किया है? दोनों पक्ष लोकतंत्र के चीरहरण के दोषी हैं!

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

रणनीति हम मतदाता भी बनाएं और अपनी सरकार बनाएं

आनेवाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं. आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है. अब वादों और इरादों पर भी जोर दिया जायेगा. इन सब चीजों के बीच पढे-लिखे लोगों और खासकर युवाओं को भी अपनी रणनीति तय कर लेनी चाहिए, कौन-सा उम्मीदवार उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है या उतर सकता है. इसका निर्णय कर ही उसे अपना मत देना चाहिए. हमें बिना जाति-धर्म देखे, सबसे योग्य उम्मीदवार का निर्णय करना है. एक ऐसा पढ़ा-लिखा नेता, जो हमारे कदम से कदम मिला कर चले, जो हमारे विकास के बारे में सोचे, जो हमारे दुख-दर्द को समझे. जरूरी है कि इस बार राजनीतिक दलों के साथ-साथ रणनीति हम मतदाता भी बनाएं और अपनी सरकार बनाएं.

उत्सव रंजन, नीमा, हजारीबाग

टैक्स रियायत का सच

सियासी तौर पर हम कितने सयाने हुए, वह चुनावी नतीजों से जाहिर नहीं होता. एक जमाना था जब सिगरेट की कीमतों से बजट आकलन होता था, फिर टीवी और बाद में कार और मोबाइल की कीमतें पैमाना तय करने लगीं. नये भारत का बजट गर्भवती महिलाओं, छोटे कामगारों और किसानों के भत्ते, पेंशन और सम्मान निधि पर सिमट गया. तालियां तो बटोर ले जाती हैं टैक्स रियायतें. इस बार तालियां खूब बजीं. पांच लाख की कमाई, डेढ़ लाख की छूट और पचास हजार की कटौती, घर कर्जे, बीमारी, बीमा कुल मिला कर बजट बम-बम जो था. शोर-शराबे में वैधानिक चेतावनी ही दब गयी. वैतनिक आय से पचास हजार कटौती छोड़ दें, तो अगली छूट के लिए 6.5 लाख की कमाई में थोड़ी भी बढ़त फिर पुराने कर ढांचे पर ले आयेगी, यानी लौट कर बुद्धू घर को आये.

एमके मिश्रा, रातू, रांची

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006, **मेल करें** : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है

कुछ अलग

पांखुरी-पांखुरी मुस्कुराता वसंत

कविता विकास

लेखिका

kavitavikas28@gmail.com

प्रकृति जिस समय अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, उसी समय जीवन का उदात्त काल होता है. वसंत वनस्पति के संवत्सर ताप का अत्यंत मनमोहक पुरश्चरण है. प्रकृति के सान्निध्य में मानव चेतना का विकास हुआ है. क्षितिज के उस पार से वासंती विभव से आप्यायित वसुंधरा को पुलक स्पर्श देने के लिए भुवन भास्कर विशेष ऊर्जा से भरे होते हैं, जो मकर संक्रांति के बाद से दिखायी देने लगता है. खेतों में सरसों खिलने लगती है. मलय ज्यों ही कलियों को छूता है, पांखुरी-पांखुरी मुस्कुराने लगती है.

परिवर्तन बाहरी है, पर मनुष्य और प्रकृति में आंतरिक एकता है. निराला का वसंत बोध ईश्वरीय है. पुण्य श्लोक रचने के लिए प्रेरित करनेवाला काल है. कवि हृदय को मुखरित करनेवाला काल. त्रिपुरासुर के विनाश के लिए जब कामदेव ने योगिराज शिव की समाधि भंग करनी चाही तो उसे वसंत का सहारा लेना पड़ा. जो वसंत कामदेव का सहायक है, वही जीवन में रत होने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित करता है और वही रंग दे वासंती चोला में आत्मोत्सर्ग के लिए भी प्रेरित करता है. सरस्वती का आह्वान सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजती हुई परंपरा का द्योतक है. वरद साहित्य और संस्कृति की वरदायिनी वागीश्वरी सरस्वती वसंत की शोभा में चार चांद लगा देती हैं. आम्र मंजरियों का पहला चढ़ावा श्वेत पद्म पर विराजमान सरस्वती को अर्पित होता है, ताकि देश की संतति परंपरा आम्र वृक्षों की शाखाओं की तरह अपने यश का चतुर्दिक विकास कर सके. वीणावादिनी के पुस्तक और वीणा धारण करने का मतलब यही है कि ज्ञान का क्षेत्र संकुचित नहीं रहे. साहित्य और संगीत सृजनात्मकता बढ़ाते हैं और मधुरम जीवन का पर्याय बनते हैं. इसी मधुरता का विस्तार है वसंत ऋतु. वसंत का आगमन वन, नदी, पोखर, जीव-जंतु, मकरंद-पराग को प्रफुल्लित करता है.

वसंत मुक्ति का प्रतीक है. तभी तो जब कली फूल बनती है, तब अपनी संकीर्णता से मुक्ति पा जाती है. वसंत का ध्येय भी यही है. यह जीवन, मुक्ति और सौंदर्यानुभव तीनों रूपों में लोक को समर्पित है. साहित्य, संगीत और स्वर की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती काल वृंत के सबसे सुंदर वसंत रूप में जब पद्मासन पर विराज हो धरती पर पहुंचती हैं, तब वासंतिक छटा अपने सर्वोत्तम शृंगार में होती है. सरस्वती श्वेतांबरा हैं, श्वेत मोक्ष और सात्विकता का प्रतीक हैं.

वसंत स्वाभाविक है और प्रकृति अनंत. वसंत केवल प्रकृति का उत्सव नहीं, समस्त ब्रह्मांड का उत्सव है. स्वर ईश्वर है और ईश्वर आनंद है. आनंद का कोई एक स्रोत नहीं है. यह एक रहस्यमय शब्द है. इसे न शब्दों में बांध सकते हैं और न सीमाओं में. महंत इस आनंद की अनुभूति पद्मिनी के खिलने में करता है, तो कवि आम्र मंजरियों के रिसाव में. खिलना, फूलना, उड़ना, चहकना और हंसना उल्लास है. यही उल्लास वसंत है. प्रकृति में जो राग है, वही मन का राग बन जाता है. चारों तरफ बस प्यार ही प्यार छलकने लगता है.

देश दुनिया से

ईयू से ब्रिटेन के अलग होने से भारत को नुकसान

आगामी 29 मार्च को यूरोपीय संसद से ब्रिटेन अलग होने जा रहा है. लेकिन ब्रिटेन की संसद में नये मतदान के बाद अगर दोनों पक्षों के बीच कोई नया समझौता नहीं होता, तो उसे बिना किसी समझौते के ही अलग होना पड़ेगा. अगर बिना किसी समझौते के यानी नो-डील ब्रेक्जिट होता है, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा. इससे यूरोप और खासतौर पर उसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को नुकसान पहुंचेगा, जिसके उत्पादों के लिए ब्रिटेन एक बड़ा बाजार है. भारत भी ब्रिटेन के अलग होने को करीब से देख रहा है. वहां निवेश कर चुकीं कई भारतीय कंपनियां चिंतित हैं. भारतीय कंपनियां ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के एक प्रवेश द्वार के रूप में देखती हैं. अब तक एक आम बाजार ने यूरोपीय देशों में इन कंपनियों की बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित की है. ब्रिटेन में 800 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार देती हैं. इन कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा और हजारों लोगों की नौकरी चली जायेगी. पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में कई भारतीय कंपनियां फली-फूली हैं. इनके अलावा ब्रिटेन के फार्मा सेक्टर में भी भारतीय व्यापार फला-फूला है. उनके लिए भी जाहिर तौर पर ब्रेक्जिट एक बुरी खबर है.

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी